मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से नई परियोजनाएं

4611. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटूभाई पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नई परियोजनाओं को आरंभ करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं का अनुमानित लागत क्या है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर: (क) से (ग) उन परियोजनाओं की एक सूची विवरण में दी गई है **(नीचे देखिये)** जिनके विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किये जाने की संभावना है। लेकिन, अन्तिम रूप में जिस परियोजना का वित्तपोषण किया जाएगा, वित्तीय सहायता की राशि और वचनबद्धता का समय—ये सब बातें परियोजना का विस्तृत ब्यौरा तैयार होने, दाता देश की तरजीह और वचनबद्धता की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।

विवरण

मध्य प्रदेश में विश्व बैंक और अन्य अभिकरणों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(मिलियन अमेरिकी डालर)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	राशि	टिप्पणी
1.	बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व	विश्व बैंक यूनिसेफ	214.5 67.8	बहुराज्यीय
2.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	विश्व बैंक	84.0	बहुराज्यीय
3.	आई०सी०डी०एस०II	विश्व बैंक	—	—
4.	नर्मदा सागर परियोजना	विश्व बैंक	420.0	—
5.	नर्मदा नदी बेसिन	विश्व बैंक	120.0	बहुराज्यीय
6.	मध्य प्रदेश में प्रारंभिक विद्यालय का निर्माण	ई०ई०सी०	—	—
7.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	विश्व बैंक	320.0	बहुराज्यीय

उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक और अन्य अभिकरणों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(मिलियन अमेरिकी डालर)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	राशि	टिप्पणी
1.	बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व	विश्व बैंक यूनिसेफ	214.5 67.8	बहुराज्यीय —
2.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	विश्व बैंक	84.0	बहुराज्यीय
3.	उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा	विश्व बैंक	—	—
4.	जनसंख्या परियोजना-VIII	विश्व बैंक	—	बहुराज्यीय
5.	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक ट्यूबवैल्स-III	विश्व बैंक	200.0	—
6.	बरेली में 500 बिस्तर वाला अस्पताल	सऊदी निधि	—	—
7.	सीतापुर में 300 बिस्तर वाला अस्पताल	सऊदी निधि	—	—

(मिलियन अमेरिकी डालर)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	राशि	टिप्पणी
8.	परिवार नियोजन में नवीनता	यू०एस०ए०आई०डी०	—	—
9.	झींगा मछलीपालन	विश्व बैंक	95.0	बहुराज्यीय
10.	उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन	विश्व बैंक	100.0	—
11.	वन्य जीवन संस्थान, देहरादून, को सहायता	यू०एन०डी०पी०	—	—

Appointment of Auditors for Loan Assistance from IRBI

4612. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of cases of loan assistance under charge of IRBI's Delhi office where appointment of Concurrent/ Internal Auditor with IRBI's prior approval have been made a loan condition;

(b) what is the number of cases where such condition was enforced;

(c) what is the methodology of selecting, authorising appointment of such auditors at I.R.B.I.;

(d) what is the number of cases where the criteria has been ignored; and

(e) what is the number of cases where any particular Auditor/firm has been given more than one such assignments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) The Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) has reported that its Delhi Office has stipulated the condition of its prior approval to appoint internal auditors in respect of 7 cases.

(b) This condition has already been enforced in respect of one case and is being enforced in respect of two more cases where disbursements have been made recently. In three cases, internal or concurrent auditors appointed by the companies arc continuing and the position will be reviewed after their term expires. In one case legal action has been initiated and hence the condition is not enforceable.

(c) and (d) As a measure of financial control and proper use of funds, IRBI stipulates the appointment of a firm of Chartered Accountants as internal/ concurrent auditor to monitor the progress of the company. For this purpose IRBI maintains a panel of names of Chartered Accountants wherefrom a few names arc suggested to the industrial compan appoint one of them whenevci IRBI decides to stipulate the condition for appointment of internal auditor. Wherever the companies are already utilising the services of internal auditors, IRBI normally allows them to retain their services provided such auditors comply with the terms of reference given by IRBI and nothing adverse is reported against such auditors. Notwithstanding, this, in certain cases the condition of prior approval of IRBI is still stipulated as a measure of stricter control to be exercised.

(e) IRBI has reported that there is no case where an assignment has been given to any particular firm in more than one case.

S.E.B.I, guidelines for setting up private mutual funds

4613. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the S.E.B.I, has outlined the broad framework of the authorisation process and selection criteria for establishing private mutual funds;

(b) if so, what are the details of the guidelines issued in this regard;

(c) what is the number of inquiries received by S.E.B.I, for establishing mutual funds; and

(d) what are the names of the